

शंकर दस्तीदार

बनाम

श्रीमती बंजुला दस्तीदार और अन्य

5 दिसंबर, 2006

(न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू)

परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 91- सामान को गलत तरीके से हिरासत में रखना - कथित हिरासत के पांच साल बाद नुकसान का दावा, समय से वर्जित है।

प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने भाई के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। अपीलार्थी को उनके आवासीय मकान के संबंध में 16.3.1983 को अपीलकर्ता ने उस कमरे को बंद कर दिया जहां प्रतिवादी नंबर 1 का सामान वाली अलमारी रखी हुई थी। एडवोकेट कमिश्नर ने सामान की सूची बनाई। इसके बाद अपीलकर्ता ने भी मुकदमा दायर किया। 24.6.1992 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुओं सहित उसके सामान को गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए 50,000/- रुपये के नुकसान का और इस आरोप पर 88,000 रुपये का प्रतिदावा किया कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की वैधता प्रभावित हो सकती है। नवीनीकरण नहीं किया गया और इस प्रकार,

उसे नुकसान हुआ। अपीलकर्ता ने मुकदमा वापस ले लिया। हालाँकि, प्रतिदावे को एक मुकदमा माना गया। यह आदेश दिया गया था। अपील पर, उच्च न्यायालय के समक्ष, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि काउंटर दावा परिसीमा के कारण वर्जित था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय ने, अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 91 किसी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति को गलत तरीके से लेने या घायल करने या गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए मुआवजे के मुकदमे के संबंध में परिसीमा की अवधि प्रदान करता है। जिस समय से अवधि शुरू होगी वह तब होगी जब संपत्ति को गलत तरीके से लिया गया या क्षति कारित की गई या जब हिरासत में लिया गया कब्जा गैरकानूनी हो गया।

1.2. संपूर्ण संपत्ति पर कब्जा 16.03.1987 को लिया गया था जब अपीलकर्ता ने कमरे में ताला लगा दिया था। प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 24.06.1992 को यानी कथित हिरासत के पांच साल बाद दायर किया गया था।

इस प्रकृति के मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 91 लागू नहीं होगा, तो अवशिष्ट प्रावधान यह तथ्य होगा कि अपीलकर्ता ने उस कमरे को बंद कर दिया था, जहां प्रतिवादी नंबर 1 से संबंधित सामान वाली अलमारी थी। संग्रहीत की जानकारी प्रतिवादी क्रमांक 1

को 16.03.1987 को थी। वह इसके बारे में जानती थी। यदि उसे अपीलकर्ता की ओर से उस कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करना था, तो उसे उक्त तिथि से तीन साल के भीतर मुकदमा दायर करना चाहिए था। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 को अपीलकर्ता की ओर से कथित गलत कृत्य के बारे में पता था। उसने पहले के मुकदमे में अधिकार जो एक दूसरे के मुकाबले की प्रकृति में एक आवेदन दायर किया। वह खारिज कर दिया गया, जिसमें उसके वाद का कारण उसके भाई से भिन्न और विशिष्ट था, जो स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के संबंध में था। जबकि दूसरा विशिष्ट चल संपत्तियों की गलत तरीके से हिरासत के लिए नुकसान के संबंध में था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा और उनके बीच एक अन्य कानूनी कार्यवाही में, एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था और उक्त कमरे के सामान की सूची तैयार की गई थी, मात्र इसलिए इससे दावा करने के लिए कार्रवाई का कोई नया कारण उत्पन्न नहीं होगा। नुकसान के लिए मामला यदि माल के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया होता तो स्थिति भिन्न हो सकती थी।

शरत चंद्र मुखर्जी बनाम नेरोड चंद्र मुखर्जी और अन्य। एआईआर (1935)
कलकत्ता 405, संदर्भित

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5609/2006

(कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.1.2005 के 2002 के एफ.ए. संख्या 71 में)

अपीलकर्ताओं के लिए प्रणब कुमार मल्लिक और एस.के. पटनायक।

प्रतिवादियों की ओर से डी. बेरा और सरला चंद्रा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

बी. सिन्हा. जे.

अनुमति प्रदान की गई।

माल की गलत तरीके से हिरासत के संबंध में प्रतिदावा करने के लिए परिसीमा की अवधि क्या होगी, यह इस अपील में शामिल प्रश्न है जो 2002 के एफ.ए. नंबर 71 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19.01.2005 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है।

अपीलकर्ता और दीप्ति दासगुप्ता प्रतिवादी नंबर 2 के पति दिवंगत कामाक्ष्य कुमार भाई हैं। बंजुला दस्तीदार, प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ उनकी बहन है. उनकी

एक और बहन थी बुलबुल दस्तीदार (जिनकी नवंबर 1987 में मृत्यु हो गई) पी-824, न्यू अलीपुर, कोलकाता में स्थित उनके आवासीय घर के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था, कथित तौर पर, अपीलकर्ता ने उस कमरे में ताला लगा दिया था, जहां प्रतिवादी नंबर 1 बंजुला 16.03.1987 को रहती थी। उक्त मुकदमे में एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके एक सूची बनाई गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 24.06.1992 को उसके सामान की गलत हिरासत के लिए नुकसान का दावा करते हुए एक जवाबी दावा दायर किया गया था। कथित तौर पर दावे की राशि इस आरोप पर की गई थी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की वैधता को नवीनीकृत नहीं किया जा सका है और इस प्रकार, उसे 88,000/- रुपये का नुकसान हुआ है, जिसके लिए दावा किया गया। उसमें कपड़ों और व्यक्तिगत वस्तुओं सहित उसके सामानों को गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए 50,000/- रुपये की क्षति का प्रतिदावा किया। हालाँकि, वाद वापस ले लिया गया किंतु प्रतिदावे को एक दावा माना गया। यह आदेश दिया गया था।

अपील में उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या उक्त प्रतिदावा परिसीमा द्वारा वर्जित था।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस आधार पर कि धारा 22 परिसीमा अधिनियम, 1963 के लागू होने पर मुकदमा चलाया जो परिसीमा से वर्जित नहीं था।

डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने हालांकि राय दी कि पूरा किया गया अपकृत्य लगातार गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा:

"...यह निरंतर गलत होने का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का निरंतर स्रोत बनाता है और कार्य करने वाले को चोट की निरंतरता के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि गलत कार्य से पूर्ण क्षति होती है तो कोई गलत कार्य नहीं होता है, क्योंकि कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है।"

अपने फैसले के समर्थन में, डिवीजन बेंच ने शरत चंद्र मुखर्जी बनाम नेरोड चंद्र मुखर्जी और अन्य एआईआर (1935) कलकत्ता 405 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया है। यह घोषणा के लिए एक मुकदमा था। उस भूमि के उपयोग के संबंध में वादी का अधिकार जिस पर मार्ग के रूप में कुछ शेड बनाए गए थे जो उसमें बाधा डाल रहे थे। उस आधार पर यह माना गया कि यह लगातार दोषपूर्ण है।

हमारी राय में क्षति के लिए मुकदमा, एक अलग स्तर पर खड़ा है - एक संपत्ति में किसी के अधिकार के आनंद के संबंध में लगातार अवरोध होना। जब किसी

निश्चित भूमि पर रास्ते के अधिकार का दावा किया जाता है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी जिस पर अपकृत्य कर्ता के पास कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, उल्लंघन जारी रहेगा। हालाँकि, यह निर्विवाद है कि जब तक गलती जारी नहीं रहती, परिसीमा अवधि का चलना बंद नहीं होता। एक बार जब अवधि चलना शुरू हो जाती है, तो यह रुकती नहीं है, सिवाय इसके कि जहां धारा 22 के प्रावधान लागू होंगे।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 68, 69 और 91 चल संपत्ति के संबंध में मुकदमों को नियंत्रित करते हैं। चोरी से खोई या अर्जित की गई विशिष्ट चल संपत्ति के लिए या पार्टी के कब्जे के संबंध में बेईमानी से दुरुपयोग या रूपांतरण जान अनुच्छेद 68 के संदर्भ में सीमा का प्रारंभिक बिंदु होगा। किसी भी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति के लिए, अनुच्छेद 69 के संदर्भ में जिस समय से अवधि शुरू होती है, वह तब होगी जब संपत्ति गलत तरीके से ली गई हो। अनुच्छेद 91 किसी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति को गलत तरीके से लेने या क्षति करने या गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए मुआवजे के मुकदमे के संबंध में सीमा की अवधि प्रदान करता है। जिस समय से अवधि शुरू होती है। वह तब होगी जब संपत्ति गलत तरीके से ली गई हो या क्षति हो गई हो या जब हिरासत में लेने वाले का कब्जा गैरकानूनी हो गया हो।

कहा गया कि 16.03.1987 को पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था जब अपीलकर्ता ने कमरे में ताला लगा दिया था। प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

24.06.1992 को दायर किया गया था यानी कथित हिरासत के पांच साल बाद इस प्रकृति के मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 91 लागू नहीं होगा, तो अवशिष्ट प्रावधान लागू होगा। तथ्य यह है कि वादी के पास उस कमरे में लॉकर था जहां प्रतिवादी नंबर 1 का सामान रखने वाली अलमारी रखी गई थी, इसकी जानकारी प्रतिवादी नंबर 1 को 16.03.1987 को थी। वह इसके बारे में जानती थी। यदि उसे अपीलकर्ता की ओर से उस कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करना था, तो उसे उक्त तिथि से तीन साल की अवधि के भीतर मुकदमा दायर करना चाहिए था। आगे। प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलकर्ता की ओर से कथित गलत कृत्य के बारे में पता था। उसने पहले के मुकदमे में *प्रो इंटरसे सुओ* की प्रकृति में एक आवेदन दायर किया। वही खारिज कर दिया गया। उसके कार्य का कारण उसके भाई से भिन्न और स्पष्ट था। एक अधिकार की घोषणा के साथ-साथ कब्जे के संबंध में था, दूसरा विशिष्ट चल संपत्तियों की गलत तरीके से हिरासत के लिए नुकसान के संबंध में था, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच एक अन्य कानूनी कार्यवाही में, एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था और उक्त कमरे के सामान की सूची तैयार की गई थी, वही, हमारी राय में, नुकसान के लिए दावा करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न नहीं करेगा। यदि माल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया होता तो मामला अलग हो सकता था।

इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

डी.जी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।